समस्या है किन्त उनका कहना यह है कि आने वाले लोगों की संख्या कम है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं और उन पर सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के बीच बैठकों में अनुवर्ती कारवाई की जा रही है।

Stranded Students in Republics of erstwhile Soviet Union

3. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 4000 Indian students are stranded in the Independent Republics of erstwhile Soviet Union as they are not getting adequate facilities for their education; and

(b) what measuers Government are taking for repatriation of those students from various Soviet Republics?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Indian students studying in the Republics of the former Soviet Union are facing some difficulties as a result of the radical economic and political restructuring that has taken place there.

(b) Repatriation of students desiring it can be undertaken as per existing Government regulations and on humanitarian considerations.

Improving the functioning of ICWA

4. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Starred Question 124 given in the Rajya Sabha on 4th September, 1991 and state:

(a) what steps have so far been taken to improve the functioning of Indian Council of World Affairs;

(b) whether complaints of alleged mal-functioning and other irregularities in Indian Council of World Affairs have been received from employees' union in ICWA:

(c) if so, whether any enquiry has been ordered; and

(d) if not, reasons for not ordering an enquiry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (d) As the ICWA is an Autonomous institution, Government are not presently associated with its functioning, and scope for an enquiry does not arise, although complaints have been received.

लीबिया से लौटे भारतीय

5. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लीबिया में रह रहे भारतीयों ने लीबिया में वर्तमान संकट जारी रहने की आशंका से घबराकर अपने परिवारों को भारत भेजना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने भारतीय परिवार स्वदेश लौट चुके हैं; और

(ग) स्वदेश लौटने के इच्छुक ऐसे भारतीयों की वीसा आदि प्राप्त करने में हर संभव सहायता देने के लिए लीबिया स्थित भारतीय राजपूत को क्या अनुदेश दिये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) कुछ भारतीय परिवार अपने सहज क्रम में लौट आए हैं। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि लीबिया से भयभीत होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं।

(ख) इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी संख्या में लोग भारत लौट आए हैं क्योंकि यह लोग सामान्य रूप से बिना किसी कठिनाई

के आए हैं इसलिए भारत के पास उनके आंकड़े नहीं हैं।

(ग) भारतीय राजदूत ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय से सलाह मशविरा करके भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों को सहायता देने की योजनाए बनाई हैं, यदि वे सामान्य तरीकों से न आ पा रहे हों तो, या उन्हें कोई खास कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो।

India's Sovereignty over Tin Bigha

6. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether in terms of modalities of leasing Tin Bigha corridor to Bangladesh as finalised through exchange of letters between the Additional Secretary, Peoples' Republic of Bangladesh and the Foreign Secretary of the External Affairs Ministry, India, the right of passage for Bangladesh through Tin Bigha area, arms and army of Bangladesh have been excluded;

(b) if not, how it would affect India's sovereignty over Tin Bigha; and

(c) how far the clause 10 of the letter agreeing to, "provide mutual judicial assistance" is in conformity with India's judicial jurisdiction over an area under its sovereignty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) No Sir, the right of passage for Bangladesh through the Tin Bigha Area does not exclude arms and army of Bangladesh, whose passage will be governed by Para 4 of the 1982 Tin Bigha Lease Agreement.

(b) It would not effect India's sovereignty over the Tin Bigha as such access would be subject to the agreed terms and modalities.

(c) Judicial jurisdiction of India and Bangladesh over Tin Bigha would be governed by Para 9 of the 1982 Tin Bigha Lease Agreement. To ensure this, mutual judicial assistance will be given by India and Bangladesh to each other to the extent necessary.

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

7. मौलाना मोबीनुल्हा खान बाजयी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेसलर संशोधन के बावजूद अमरीका पाकिस्तान को सैन्य तथा अन्य प्रकार की सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या रणनीति अपनाने का विचार रखती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.एडार्डो फेलोरियो) :(क) और (ख) अमरीकी सरकार का कहना यह है कि प्रेसलर संशोधन पाकिस्तान को सैनिक उपकरणों की "वाणिज्यिक" बिक्री पर लागू नहीं होता है। अमरीकी सरकार के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1991 में इस प्रकार की बिक्री 22.781 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर थी।

(ग) सरकार इन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत के सुरक्षा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है और भारत की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

Nuclear option for India

8. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether 'Nuclear option' is a closed one or an open option for India;

(b) if it is 'closed one' what are the reasons therefor; and